to Rajya Sabha and Lok Sabha Secretariats for construction of houses for their employees ;

(b) if so, when and where ;

(c) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Indian Express dated the 15th March, 1992 captioned 'Governement staff face acute housing problems' ;

(d) if so, what is Government's reaction thereto ; and

(e) the progress made so far in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) No, Sir.

(b) In view of (a) above question does not arise.

(c) Yes Sir.

(d) and (e) During the Eighth Plan period the Government proposes to construct more flats in the general pool for Central Government Employees. The progress in this regard would depend on the extent of funds allocated for this purpose from year to year.

Action taken on CAG'S Report

2536. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state what action has been taken by Government on CAG's report regarding use of over 80 per cent of sub-standard construction material by DDA for its ambitious Rohini scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : DDA have reported that samples are taken only in cases where preliminary investigations indicate possible sub-standard material/works.

As per CAG report, 366 samples were taken for testing but as per DDA records 264 samples were taken by the Quality Control Cell. Out of these 264 samples collected by the Quality Control Cell, 202 samples failed. Action taken for 202 samples is as under :—

(i) Material got removed work redone	41
(ii) Material accepted at reduced rates	144
(iii) Action in process . .	17
Total :	202

"हुडको" से उत्तर प्रदेश की आवासीय एजेंसियों को ऋण दिया जाना

2537. श्री ईश दत्त यादव : क्या कृपा शहरी विकास मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की आवासीय एजेंसियां राज्य में आवासों के निर्माण और मूलभूत शहरी सुविधाओं में सुधार के लिए 1990–91 से हुडको से ऋण प्राप्त करने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्र की आवासीय एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न ऋण प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है अथवा किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1990-91 से और 30.6.1992 की स्थिति के अनुसार हुडको ने 3.67 लाख रिहायशी एककों और 1.34 लाख कम लागत के स्वच्छता एककों के निर्माणार्थ 651.02 करोड़ रुपये (शहरी अर्धसंरचना के निमित्त 93.33 करोड़ रुपये सहित) की ऋण धनराशि वाली उत्तर प्रदेश की विभिन्न एजेंसियों की 386 स्कीमें अनुमोदित की हैं।

(ख) और (ग) 8.7.92 की स्थिति के अनुसार प्रक्रियाधीन उत्तर प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	स्कीम का प्रकार	स्कीमों की संख्या	हुडको ऋण धनराशि (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1.	शहरी आवास स्कीमें	89	163.57	मूल्यांकन मुद्दों के अनुपालन के लिए एजेंसियों के पास विचाराधीन।
2.	शहरी आवास स्कीमें	14	14.46	क्षेत्रीय तकनीकी समिति की मंजूरी की प्रतीक्षा।
3.	भूमि अधिग्रहण स्कीमें	14	78.94	मूल्यांकन मुद्दों के अनुपालन के लिए उधार लेने वाली एजेंसियों के पास विचाराधीन।
4.	शहरी अर्धसंरचना स्कीमें	2	13.20	हुडको के मुख्यालय में मूल्यांकनाधीन।
5.	—वही—	23	105.08	तकनीकी अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए उधार लेने वाली एजेंसियों के पास विचाराधीन।
6.	वाणिज्यिक स्कीमें	2	5.93	मूल्यांकन मुद्दों के अनुपालन के लिए उधार लेने वाली एजेंसियों के पास विचाराधीन।